(ग) क्या इस कारखाने को कुछ पूर्व शर्तों के आधार पर कारखाना लगाने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इन शर्तों का पालन किया गया है;

(ङ) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में अन्य स्थानों पर सीमेंट के कारखानों को स्वीकृति देने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन सी शर्तें हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते हुए विशेष शर्तें और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय जैसे हरित पट्टी का प्रावधान करना, उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना, प्रदूषण निगरानी स्टेशन स्थापित करना, अनुबन्ध शर्तों को कार्यान्वित करने की देखरेख के लिए निगरानी कमेटी को गठित करना इत्यादि निर्धारित किए गए थे। जैसाकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, सीमेंट प्लांट अनुबन्ध शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

(ङ) हिमाचल प्रदेश से सीमेंट प्लांट के लिए कोई भी नया प्रस्ताव इस मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Afforestation in the Country

390. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether annual rate of afforestation in the country has been fixed;

(b) if so, the details thereof and when was such a rate fixed;

(c) whether the target of annual rate of afforestation achieved has been maintained;

(d) if not, what has been the drop in the annual rate of afforestation; and the reasons thereof; and

(e) the steps taken to achieve the fixed annual rate of afforestation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (e) Afforestation and tree planting activities are undertaken throughout the country under the Twenty Point Programme. The targets are fixed annually subject to the overall availability of funds in the Central and State Plans. The details of tragets and achievements during the last three years are as given below:

(seedling in lakhs)
(area in hectares)

Year	TARGETS		ACHIEVEMENTS	
	Seedling Distribution	Area Coverage	Seedling Distribution	Area Coverage
1992-93	14500	10,64,000	12450.87	10,62,226
1993-94	13509	11,65,300	11097.61*	9,63,888*
1994-95	11835.10	10,31,320	10367.51*	9,45,367*

*tentative

The total fund availability for afforestation activities has not increased adequately commensurate with the targets and in keeping with increasing costs, particularly the wage-rates.

बिहार में नए खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किया जाना

391. श्री जनार्दन यादव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

बिहार में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में आम और लीची के उत्पादन के आधार पर नए एकक लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के संबंध में राज्यवार सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:—

	यूनिटों की संख्या
चावल मिल	4872
रोलर फलोर मिल	58
फल तथा सब्जी उत्पाद	41
मृदु वातित जल	12
दूध उत्पाद	2
संगठित बिस्कुट यूनिट	1
मांस प्रसंस्करण	1

(ख) और (ग) यह मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है।

बिहार में दलितों और पिछड़ों की हत्याओं के मामले

392. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1995 से जून, 1995 तक बिहार में हुई सामूहिक हत्याओं में कितने दलितों और पिछड़ों की हत्या हुई; और

(ख) इन हत्याओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या योजना बना रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) और (ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधक कारखानों का निजीकरण

393. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात और स्वदेशी मांग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में नए तेल-शोधक कारखानों की स्थापना हेतु कुछ इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तेल शोधक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन तेल शोधक कारखानों को स्थापित किया जाना है;

(ग) निजी क्षेत्र के अंतर्गत अब तक कितने तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई है और की जा रही है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है एवं उनका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है; और

(घ) प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने कब तक कार्य/उत्पादन करना शुरू कर देंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने निजी/संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है।